every airport, Private airlines are given priority than Government airlines for landing as well as take-off. It is a complaint that we are receiving, and it is our personal experience also. I would like to know from the hon. Minister whether it is true.

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति जी, आपका धन्यवाद कि आपने हमारी तीसरी महिला सदस्य को यह मौका दिया है कि वे क्वैश्चन पूछें ।...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: जब 33 परसेंट होगा, तब आप क्या कहेंगे? ...(व्यवधान)...

श्री प्रफुल्ल पटेल: अच्छा है।...(व्यवधान)... I am thanking on your behalf Brindaji. I am on your side. Sir, it is our endeavour to upgrade our air traffic management systems and communication systems at the airports. For this, we have entered into various agreements. We have even signed an MoU with the United States, the FAA (Federal Aviation Authority). It has now set up its own office in Delhi to help and assist us in upgrading our systems. We are now working closely with various agencies internationally. On safety of helicopters, we now have a representative of the European Union here who is guiding us. There are various aspects. I may not have the information readily available with me on this particular issue that you have mentioned, but if you have any question, please, address it to me. I will try to satisfy you in writing.

श्री सभापति: ठीक है। नेक्स्ट क्वैश्चन।

रांची विमानपत्तन का विकास

*363. **श्री अजय मारू:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या झारखंड की राजधानी रांची स्थित विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा तथा इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार से इस योजना के लिए सहयोग प्राप्त हो रहा है; और

(घ) इस योजना को कितने वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल्ल पटेल): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) से (घ) झारखण्ड राज्य सरकार का मौजूदा रांची हवाई अड्डे के विकास तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रस्ताव है। बहरहाल, प्रस्तावित योजना, यातायात सम्भाव्यता, भूमि की उपलब्धता तथा एयरलाइन प्रचालकों द्वारा प्रत्याशित आवश्यकताओं के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा भूमि के प्रावधान तथा लागत की भागीदारी तथा इसके कार्यान्वयन सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा॰वि॰प्रा॰) तथा झारखण्ड राज्य सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने पर निर्भर करती है।

Development of Ranchi Airport

†*363. SHRI AJAY MAROO: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether the Airports Authority of India has formulated any plan to upgrade the airport at Ranchi, the Capital of Jharkhand, to international level;

(b) if so, by when the plan would be taken up alongwith the estimated cost thereof;

(c) whether State Government is extending its cooperation to the scheme; and

(d) the number of years the scheme would take for its completion?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI PRAFUL PATEL): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) to (d) State Government of Jharkhand has proposed to participate in the development and modernisation of the existing Ranchi Airport. However, the proposed plan is contingent to the signing of Memorandum of Understanding (MoU) between Airports Authority of India (AAI) and State Government of Jharkhand including provision of land by the State Government and sharing of cost and its implementation depends upon traffic potential, availability of land and requirements proposed by the airline operators.

†Original notice of the question was received in Hindi.

श्री अजय मारू: आपका धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं आभारी हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री नंदी येल्लैया: सर, आपने कहा था कि आपको चांस दूंगा ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इस बार चांस दूंगा ...(व्यवधान)... क्वैश्चन एक-सा ही है। There is no difference between the two questions.

श्री नंदी येल्लैया: हम काले हैं, तो क्या हुआ, हम भी मैम्बर हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आपका क्वैश्चन आ गया है ...(व्यवधान)... इस बार पहला सप्लिमेंटरी आप ही पूछेंगे।...(व्यवधान)...

श्री अजय मारू: महोदय, मैं आभारी हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया है कि झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट को विकसित और अंतराष्ट्रीय स्तर का किए जाने की योजना है। बाकि के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा कि झारखंड सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही उसकी योजना निर्भर करती है। उन्होंने यह भी बताया है कि यातायात वृद्धि पर आगे की योजना निर्भर करती है। लेकिन महोदय, एक-दो वर्ष पहले एक सर्वे आया था, जिसमें जितने नॉन-मेट्रो एयरपोर्ट्स हैं, अगर उनमें यातायात की वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा रांची में यातायात की वृद्धि हुई थी। महोदय, मुम्बई और दिल्ली के एयरपोर्ट्स के अलावा केन्द्र सरकार ने 35 नॉन-मेट्रो एयरपोर्ट्स को उच्च-स्तरीय बनाने का निर्णय लिया है और उसके अन्तर्गत 8 हजार करोड़ की योजना है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसमें रांची एयरपोर्ट शामिल है और झारखंड सरकार से इस समझौते पर कब तक हस्ताक्षर कर लिए जाएंगे?

श्री प्रफुल्ल पटेल: सभापति जी, हमारे साथी ने विशेषकर जो झारखंड और रांची के विषय में बात कही है, निश्चित रूप से रांची हर दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। रांची न केवल एक नए राज्य की राजधानी है बल्कि वहां पर एकोनोमिक एक्टिविटीज, नए उद्योग, विशेषकर माइनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे नए उद्योग लगने की संभावना भी है, इसलिए कहीं भी यह प्रश्न नहीं है कि रांची का अपग्रेडेशन जल्द से जल्द और अच्छी तरह से नहीं होना चाहिए। यह होना ही चाहिए। दूसरा, जो 35 नोन-मेट्रो एअरपोर्ट की योजना है, उसमें रांची का निश्चित समावेश किया गया है। आप जो बात कह रहे हैं रांची की, इसमें हमारी वहां की सरकार के साथ, वहां के मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक-दो बार बातचीत हुई है। हमारी योजना के तहत तो हम निश्चित रूप से काफी मात्रा में रांची का अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, जिसमें 9000 फीट का रनवे है, जिस पर बड़े जहाज भी उतर सकते हैं, नया टर्मिनल, अच्छी सारी सुविधाएं, सब कुछ है, लेकिन वहां की सरकार की इच्छा थी कि इससे भी और अधिक अच्छा किया जाए। हमने कहा है कि हमारे ट्रेफिक प्रोजेक्शन के हिसाब से हम यह चाहते हैं और आप ज्यादा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ राशि भी दे सकते हैं और उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें एमओयू करने की बात सामने आई है, लेकिन अभी इसमें कोई फाइनल, अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

श्री सभापति: अंतिम फैसला जल्दी कर दीजिए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, अब वहां की सरकार चाहती है कि हम इसको और अधिक अच्छा बनाएं। अगर पैसे का प्रावधान करके वह हमको देती है, तो हम उसका स्वागत करेंगे और किसी भी राज्य की सरकार से स्वागत करेंगे।

श्री अजय मारू: सभापति महोदय, 35 नोन-मेट्रो सिटीज में जो डवलपमेंट की बात हो रही है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रांची एअरपोर्ट के पास 100 एकड़ ऐसी जमीन है, जिस पर सेना और एअरपोर्ट अथोरिटी का विवाद चल रहा है, उस विवाद के बारे में मंत्री महोदय को क्या जानकारी है?

श्री सभापति: ठीक है, बस हो गया।

श्री अजय मारू: महोदय, इसमें और सप्लीमेंटरी नहीं होनी, इसलिए मैं यह पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं। बहुत आ रही हैं। आप अपना प्रश्न जल्दी कर लीजिए।

श्री अजय मारू: महोदय, इस प्रश्न के बारे में जानना चाहूंगा कि जो वहां नोन-मेट्रो सिटीज के पास मल्टीप्लेक्सेस और अन्य सुविधाएं देने की बात की गई है, उसमें क्या रांची एअरपोर्ट भी है?

श्री सभापति: 'हां' या 'न' में ही कह दीजिए, माननीय मंत्री जी।

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, यह जो डिफेन्स और एअरपोर्ट अथोरिटी की बात है, मैं इसकी जानकारी आपको अलग से भेज दूंगा।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री प्रफुल्ल पटेल: लेकिन यह जो रनवे की और अधिक लंबाई वहां की सरकार चाहती है, तो उसके लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से जमीन की जरूरत पड़ेगी। अगर वह काम होता होगा, तो निश्चित रूप से हम रनवे की और अधिक लंबाई का जैसा वह चाहते हैं, उसके बारे में कर सकते हैं।

श्री सभापति: श्री नंदी येल्लैया। ...(**व्यवधान**)...

श्री नंदी येल्लैया: सर, केवल तीन मिनट हैं। सर, अभी जो है ...(**व्यवधान**)... हमारे माननीय मंत्री जी, हैदराबाद के अंदर जो है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप उनको बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिए। ...(**व्यवधान**)... I won't allow. Nothing will go on record.

श्री नंदी येल्लैया: सभापति महोदय, ऐसा हो गया है कि एअरपोर्ट की हालत जो है, रेलवे स्टेशन से भी बदतर है। एग्जाम्पल के लिए हैदराबाद के अंदर, मैं कल सहारा एअरलाइन्स से आया था,

आने के बाद जो है, कल ही एक घंटा मुझे ऊपर रहने का मौका मिला। अब अगर फर्ज करो, किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, कोई अगर अचानक बीमार हो गया, किसी को अगर कोई प्रोब्लम हो गई, तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? मैंने एक दफा सुना था कि वेंकैया नायडु साहब दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे थे, उनकी अचानक तबीयत खराब होने से उनका फ्लाइट दुबारा रिटर्न किया गया। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक-एक घंटा, डेढ़-डेढ़ घंटा अगर आप ऊपर लटकाएंगे और अचानक किसी आदमी की तबीयत खराब हो गई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? ...(व्यवधान)

श्री प्रफुल्ल पटेल: सर, ईश्वर न करे कि कभी किसी यात्री की तबीयत खराब हो। वैसे निश्चित ही उसके लिए पायलट को अधिकार है कि वह इमीडिएट मैसेज भेजे और उस हवाई जहाज को प्राथमिकता देकर उतारा जा सकता है। यह न केवल उसी एअरपोर्ट पर, बल्कि यदि कोई फ्लाइट यहां से चैन्नई भी जा रहा हो, रास्ते में किसी यात्री की तबीयत खराब होती है, तो उसके लिए प्राथमिकता देकर उसे रास्ते में भी किसी हवाई अड्डे पर उतार सकते हैं, उसका भी प्रबंध किया जा सकता है।

MS. MABEL REBELLO: Sir, today's *Times of India* says, "New look for 35 regional airports". Sir, Ranchi is also included in these 35 airports. Sir, Ranchi has got additional surplus land there. I am told that they have almost taken a decision to develop this land commercially. I would like to know: What the hon. Minister is planning to do? Is he going to give it to the private sector for development? What are the projects that he is going to bring and also the amount that will be spent? And by when, he is going to develop the surplus land?

SHRI PRAFUL PATEL: Sir, surplus land is not yet defined in any particular airport. First we have to decide the operational requirement of a particular airport before we are able to decide what is surplus land. But as regards these non-metro airports, there is a broad thinking that we must develop hotels and other facilities at these airports. In fact, many small cities, where there is lack of housing facilities and shortage of hotels, will benefit and become tourist destinations. Shrimati Ambika Soni is sitting here. She has been saying herself that is hotels are developed at smaller airports, it would be a good thing to boost tourism and develop the economy of that State.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.